existing export policy on cotton under which 5 lakh bales of cotton are released at the beginning of the cotton season. Subsequent releases are made after making the assessment of the cotton's demand and supply situation, exportable surplus etc. While releasing quotas for exports, the Government strives to balance the interests of the cotton farmers on the one hand and those of the handloom/powerloom and the mill sector on the other.

Dumping of Low-cost Textiles in the World Market by China

5558. SHRI RAM NATH KOVIND : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of China dumping in a big way of its low cost textile and clothing products in the world market;

(b) if so, whether Government have visualised its effect on India's textile export to European and other countries; the details;

(c) whether Government propose to draw up any strategy to meet this challenge and restore confidence in indigenous industry; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) Government have no specific information in this regard.

(b) to (d) Do not arise.

Ceiling on Cotton Stocks

5559. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether the Textile Commission has imposed a ceiling on cotton stocks to be held by textile mills, the cotton trade, ginning and processing factories etc;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the textile mills in the country are not coming under increasing pressure from Government to make available at least 10,000 bales of hank yarn at reduced prices to the decentralised sector during April, 1994 to tide over the crisis facing the handloom sector and failing in that respect Government would ban the yarn exports; and

(d) if so, the details thereof and reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) *In the case of manufacturers*—stocks to be held not in excess of three month's average consumption.

In the case of cotton, ginning and pressing factory and person (other than agriculturists)—a quantity of cotton pressed or unpressed not more than 110% of the quantity held on the last date of the corresponding month of the previous year or 100 quintals by weight, whichever is more.

(c) to (d) Indian Cotton Mills Federation (ICMF) have agreed to make available 10 million kgs. of hand yarn to handloom weavers at subsidised rates through cooperative societies all over the country between March-August, 1994.

हथकरघा उद्योग को धागे की आपूर्ति

5560. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा उद्योग के सामने जो सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल के उपलब्ध होने में कठिनाई है :

(ख) यदि हां, तो हथकरघा उद्योग को धागे की आपूर्ति करने की विद्यमान व्यवस्था क्या है:

(ग) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग को दिए जाने वाले धागे पर राज सहायता प्राप्त है :

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार को इस धागे की काला-बाजारी करने और अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के सम्बन्ध में समाचार प्राप्त हुए हैं: और

(ङ) यदि हां, तो इस विनिर्दिष्ट धागे का प्रयोग केवल हथकरघा उद्योग में किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) यद्यपि कई विशेष स्थानों पर विशेष प्रकार के धागे की आवश्यकता और मांग में संतुलन नहीं हुआ होगा लेकिन हथकरघा क्षेत्र में कच्चे माल की कोई कमी नहीं है।

(ख) राज्य हथकरघा अभिकरण जैसे शीर्ष समितियां, राज्य हथकरघा विकास निगम और प्राथमिक समितियां हथकरघा बुनकरों को सूत सप्लाई करती है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी इन प्रयासों में अपना योगदान देता है। सूत प्राइवेट व्यापारियों तथा मास्टर बुनकरों को भी दिया जाता है।

(ग) प्लेन रील हैंक यार्न पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता जबकि क्रोस रील हैंक यार्न पर रियायती दर से शुल्क लिया जाता है। सूत के शुल्कों में हाल ही की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने एक समय अल्पावधिक उपाय के रूप में रियायती शुल्कों में हैंक यार्न की सीमित मात्रा की सप्लाई करने की एक योजना तैयार की है।

(घ) ऐसी कई रिपोर्ट मिली हैं कि क्रोस रील हैंक यार्न पावरलूम द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) क्रोस रील हैंक यार्न पर रियायती उत्पाद शुल्क के दुरुपयोग से बचने के लिए रियायत केवल हथकरघा अभिकरणों द्वारा सूत की खरीद पर ही उपलब्ध होती है।

वस्त्र व्यापार पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाना/कम किया जाना

5561. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और यूरोपीय संघ भारत से कपड़ा व्यापार में सीमा शुल्क को समाप्त करने/उसकी दर को कम करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अमरीका की क्या मांग है और क्या सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) बाजार में प्रवेश दिलाने सम्बन्धी उरुग्वे दौर की वार्ताओं के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ही भारत से आग्रह करते रहे हैं कि वह वस्त्रों और क्लोदिंग मदों के अपने शुल्कों को उस स्तर पर बन्धित करे जिन स्तरों पर वे वास्तविक रूप से व्यापार होने की संभाव्यता की दृष्टि से उचित तथा उपयुक्त समझते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ दोनों से ही स्वतः यह प्रयास कर रहा है कि वे उसके वस्त्र तथा क्लोदिंग उत्पादों के लिए अपने बाजार में प्रवेश पाने के बेहतर अवसर प्रदान करें। भारत को पारम्परिक संतोषजनक समाधान ढूंढने की दृष्टि से वस्त्र क्षेत्र में बाजार में प्रवेश दिलाने के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के साथ और वार्ताएं करनी है।

Nationalisation of Sick Textiles Mills

5562. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to nationalise fifteen sick textile mills;

(b) if so, the reasons of their nationalisation instead of privatising them;

(c) the liability of each of these mills; and

(d) the future plans in respect of sick textile mills ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The modernisation/rationalisation plans prepared by the Textile Research Associations for the revival of NTC mills have been endorsed by the Special Tripartite Committee. The Special Tripartite Committee on the NTC has also unanimously recommended nationalisation of the taken over mills. A statement indicating the liability of each of these 15 mills is enclosed (*See* below). These plans shall require the approval of Board for Industrial and Financial Reconstruction under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985 after it is approved by the Govt. before they can be implemented.

Statement

Liabilities of Non-Nationalised Mills as on 31-12-1993

S. No.	Name of the Mills	Amount (Rs. in crores)